MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Amar Pal Maurya.

Demand for running of superfast and Vande Bharat trains from Sheikhpura district of Bihar and its surrounding stations

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं बिहार प्रांत के शेखपुरा जिले से आता हूँ। शेखपुरा, बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री, आदरणीय श्रीकृष्ण सिंह जी का गृह जिला भी रहा है। वर्तमान NDA सरकार के कार्यकाल में वहां विकास के बहुत से कार्य हुए हैं। शेखपुरा जिला हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्त्व में आकांक्षी जिलों में शामिल है। शेखपुरा एवं उसके आसपास के जिलों के बहुत सारे बच्चे दिल्ली, पुणे और कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं एवं बहुत सारे लोग रोजी-रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों को बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि गोड्डा-पुणे हमसफर एक्सप्रेस का ठहराव शेखपुरा में हो तथा किउल जंक्शन से लखीसराय-शेखपुरा, नवादा-गया होते हुए दिल्ली, कोटा एवं मुंबई के लिए एक superfast ट्रेन चलाई जाए एवं गया से नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, किउल,जमुई होते हुए हावड़ा के लिए वन्दे भारत ट्रेन और गया-नवादा, शेखपुरा, किउल, जमालपुर, भागलपुर होते हुए Maldah टाउन तक एक वन्दे भारत ट्रेन चलाने की कृपा की जाए, जिससे बिहार के शेखपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, गया एवं झारखंड के बहुत सारे लोगों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Shambhu Sharan Patel.

Need for Regulation of Private Detective Agencies

SHRI KESRIDEVSINH JHALA (Gujarat): Sir, private detective agencies are on the rise, catering to needs from personal investigations like infidelity and background checks to corporate inquiries such as fraud and due diligence. These agencies offer valuable services, also pose substantial threats to personal identity and information security. The lack of stringent regulatory framework has aggravated concerns, leading to potential misuse and abuse of data.